

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक **224**/2 ई0व0भू0
सेवा में,

दिनांक **22**/01/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जग्यूडाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/11/2019/एफ0सी0/1199 दिनांक 09.09.2020.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी -प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं0 1 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जेंहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.8684 है0 ग्राम किलपारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 16,41,547.00 मात्र (रू0 सोलह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ सेंतालीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021032417601145 Dtd 24.03.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.8684 है0 ग्राम किलपारा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 23/छब्बीस-02 वन(क्ष0वृ0)/2023-24 दिनांक 20.01.2024 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-1।)

डिस्पेंसर
23/1/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

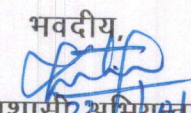
ग) वन भंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।		कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।	
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य		
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA न0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिदेशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत: 2.4342 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।		एन0पी0वी0 की धनराशि	UTR No. SBINR52021032417601145 Dtd 24.03.2021 द्वारा रू0 15,99,269.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख निरानवे हजार दो सौ उनसत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न-2)।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता	(प्रमाण पत्र संलग्न-3)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	
6	State Govt. will submit the VLC proceedings of village Simayal.	VLC proceedings of village Simayal is enclosed in 5 copies. (प्रमाण पत्र संलग्न-4)।	
7	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. Will strictly monitor and ensure the no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	गाईडलाइन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के कम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा)	
8	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।	

9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न-5)
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं0-54 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

 अधिशासी अभियंता, 24
 प्रान्तीय खण्ड, नो० 10/10/10
 बागेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर
CBP 0046

पत्रांक - 642 / कैश,
सेवा में,

दिनांक 24-3-21

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम
आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,
लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं0- 285816 दिनांक 19.03.2021 ₹ 3240816.00 मात्र
की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0- 150896116904149 IFSC Code- CORP0000371 में
NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- बैंकर्स चैक सं0-285816 दिनांक 19.03.2021 ₹ 3240816.00 मूल में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

पत्रांक :- / कैश, तद दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनाार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

UTR
SBINR52021032417601145
24/03/2021

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।



AGENCY COPY

यूनियन बैंक
अॉक सुंडियाUnion Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-03-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116904149
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/11/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	3240816/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Forty Thousand Eight Hundred
and Sixteen Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक
अॉक सुंडियाUnion Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-03-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116904149
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/11/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	3240816/-

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Forty Thousand Eight Hundred
and Sixteen Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com U.T. R. No-

(SBINR 52021032417601145)

Dt - 24/03/2021

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com
दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 1116 / 12-2
सेवा में,

बागेश्वर, दिनांक : 08/10/2020

विषय - अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

महोदय, जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जन्यूडाबांस मोटर रोड के निर्माण हेतु 2.4342 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु (प्रस्ताव सं-16904/2015)

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/११/२०१९/एफ०सी०/११९९ दिनांक ०९.०९.२०२०।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क-९७२/३-५-२ दिनांक २१.११.२०१७ के द्वारा निर्धारित दरो के कम में वर्ष २०२०-२१ के वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	2.4342 है०	5	0.3	6,57,000.00	15,99,269.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	4.8684 है०	"--"	"--"	3,37,184.00	16,41,547.00

RM. 2402 / 25 व. म.

DMO/AC(I)/वन प्रभाग बागेश्वर

8/10/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

आदेश.

तहसीलदार कपकोट के पत्र संख्या: 106 / आर0के0-विविध / 2023-24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत नरगोली- सिमायल-भण्डारीसेरा- सलिया- जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342है0 की दुगुनी 4.868है0 भूमि, जो ग्राम किलपारा, बदियाकोट, तहसील कपकोट के गैर ज0वि0 श्रेणी 9(3)ख(2) के ख0खा0 संख्या-80 के पैमाईशी खेत नं0 01 के रकवा 2.166है0 एवं पैमाईशी खेत नं0 05 मध्ये रकवा 2.702है0 इस प्रकार कुल 4.868है0 भूमि को शासनादेश संख्या: 8बी/यू0सी0पी0 / 06/11/2019/एफ0सी0/1199 दिनांक 09.09.2020 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनुराधा पाल)

जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या: 23 / छब्बीस-02/वन(क्ष0वृ0)/2023-24 दिनांक 20/01/2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी, कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
04. तहसीलदार कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि को हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण-पत्र के वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)

जिलाधिकारी, बागेश्वर।

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No- None

Dated- 30-10-2013

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.4342 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Nargoli-Simayal-Bhandarisa-Saliya-Jagurabas motor road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Nargoli, Simayal, Bhandarisa, Saliya and Kafali villages in Kanda Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.4342 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 30-10-2013

Signature

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

1.6
प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीरेखा-सलिया-जंग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारीरेखा-सलिया-जंग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 0.00 है० आरक्षित वनभूमि, 0.4624 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 1.9718 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री के०एस०रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री कुन्दर सिंह कोरा	बी०डी०सी० क्षेत्र टकन	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरगोली-सिमायल-भंडारीरेखा-सलिया-जंग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारी-सलिया-जग्यूडाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीखेड़ा-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित नरगोली-सिमायल-भंडारीखेड़ा-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण
विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार
परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही
है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 30.10.2015

(भूपाल सिंह मुन्नाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध करवा जायेगा।

1.6
प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-
सलिया-जग्युड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-सलिया-जग्युड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.11.15 के सम्मेलन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एवं लोक निर्माण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि०३०/जनपद-बागेश्वर

.....
नरगोली
वन पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

.....
ह०/
ग्राम पंचायत नरगोली
वि० ३०/जनपद बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-मंडारीगांव-
सलिया-जग्गुडाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 21/10/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नरगोली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मानिल शैलेला	Kaulela
2	महेन्द्र शैलेला	Butele
3	मानिल शैलेला	Omendra
4	देवान राय	देवान राय
5	माधव नन्द पन्त	Omendra
6	नवीन चन्द पन्त	मन्त
7	अमित पन्त	Rit
8	अपेन्द्र सिंह	अपेन्द्र
9	बुकाट सिंह	बुकाट
10	न. प. मन्त	मन्त
11	लोपती देवी	गजपति
12	मनोरा शैलेला	देवती देवी
13	सावित्री शैलेला	Butele
14	श्री ३०० शैलेला	सावित्री शैलेला
15	मन्त	मन्त
16	मन्त	मन्त
17	मन्त	मन्त

(18) दुष्पा शैलेला

ग्राम पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

मन्त
सरपंच
ग्राम पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

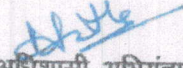
दुष्पा शैलेला
ग्राम पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-मंडारीमेठ -
सलिया-जग्यूड़ाबांस मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/
भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की
बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &

CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/११/२०१९/एफ०सी०/११९९

दिनांक: ०९/०९/२०२०

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1314/x-4-18/1(177)/2018 दिनांक 08.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16904/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.08.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं० 01 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक

30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4342 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6- State Govt. will submit the VLC proceedings of village Simayal.

Yash B

19 JAN 2024

कार्यालय तहसीलदार कपकोट, जनपद बागेश्वर।

संख्या 106 / आर0के0-विविध / 2023-24

दिनांक/18 जनवरी, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 50/छब्बीस-3(19-20)वन

518 19.1.24

विषय :- जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जन्यूडावांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 50/छब्बीस-3(19-20)वन (क्ष0वृ0)/2023 दिनांक 09.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीसेरा-सलिया-जन्यूडावांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम किलपारा की सिविल सोयम की दुगुनी 4.868 है0 भूमि हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट से जाँच करायी गयी। प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक, बदियाकोट की आख्या अनुसार ग्राम किलपारा, बदियाकोट के गैर ज0 वि0 श्रेणी 9 (3) ख(2) के ख0खा0 संख्या 80 के पै0 खेत नं0 01 के रक्वा 2.166 है0 एवं पै0 खेत नं0 05 मध्ये रक्वा 2.702 है0 इस प्रकार कुल 4.868 है0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न- 08 पृष्ठ मूल में।

भवदीय,

तहसीलदार,

कपकोट।

मेका कटर

गाम बिलापारा २०३० मि० देव बदिपारा लहो कपकोट मजदूर कोरणा
विषय $\Rightarrow$ नरकोली - सिमाना - मजदुरी देव - बलिण - मजदूरकोट कोट मजदुर देव लहो बिलापारा
सहित बलिण बलिण

संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
१	२.१६६	८०	मजदूर	०१	२.१६६	८०	मजदूर	मेका
०५	२.७८०			०५ मजदूर	२.७०२			मेका बलिण बलिण मेका बलिण - मजदूर देव मेका बलिण देव देव देव देव मेका बलिण देव
			मेका	०२	४.८६८			

मेका

मेका कटर मेका बलिण

मेका
मेका
मेका
मेका
मेका

गण	सालेदार को	पुन	रकबा	लागा	विवरण
संख्या	मान	क	लखा		

महोदय
कासलहे लेण्ड विभा /
Guna
11/01/2024
दिपाके
अपरा
आगे 291

ਅਨੰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਰਿਹਾ।

17/01/2024
अनुसूचित
जनता
अनुसूचित